केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र

जलांश

खंड 5, अंक 04, नवंबर- 2022

विषय सूची

- पोलावरम सिंचाई परियोजना के कारण पड़ोसी राज्यों में जलमग्नता से संबंधित तकनीकी मुद्दे
- जयपुर में 10-12 अक्टूबर, 2022 को INCOLD द्वारा आयोजित "अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन" में तकनीकी पेपर प्रस्तुति
- राजस्थान फीडर/इंदिरा गांधी नहर के विभिन्न मुद्दों का आकलन करने के लिए समिति
- सरस्वती नदी पुनरुद्धार परियोजना, हरियाणा
- ड्रिप-II योजना और एनडीएसए मुद्दों से संबंधित समस्याओं पर चर्चा करने के लिए सचिव (डब्ल्यूआर) की अध्यक्षता में बैठक हुई
- रेणुकाजी बांध परियोजना, हिमाचल प्रदेश-भूवैज्ञानिक पहलुओं को सुलझाने के लिए के.ज.आ., भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण(जीएसआई) और हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन (एचपीपीसीएल) के बीच संयुक्त बैठक
- साप्ताहिक विवरण
- "बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021" की धारा 54 के तहत मसौदा नियम / विनियम तैयार करने के लिए उप-समिति की 7वीं बैठक
- पीएमकेएसवाई-एआईबीपी परियोजना के लिए स्क्रीनिंग समिति की चौथी बैठक
- श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ. को आईसीआईडी के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया
- पांचवां भारत–यूरोपीय संघ जल मंच
- एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया में 24वीं आईसीआईडी और 73वीं आईईसी बैठक में के.ज.आ. के अधिकारियों की भागीदारी
- आयन क्रोमैटोग्राफ पर कार्यशाला
- शोध पत्र प्रस्तुत करने पर आईआईटी निदेशकों के साथ बैठक
- 31.10.2022 तक योजनाओं की वित्तीय प्रगति
- देश में बाढ़ की स्थिति-अक्टूबर 2022
- जलाशय निगरानी
- अक्टूबर-2022 के दौरान एन डब्ल्यूए, पुणे द्वारा प्रशिक्षण गतिविधि
- डेटा कॉर्नर- के.ज.आ. बेसिन
- गेलरी
- इतिहास- महानदीजलाशय परियोजना

डॉ. आर.के. गुप्ता
अध्यक्ष

संदेश

नवंबर का महीना मेरे कार्यकाल का आखिरी कार्यरत महीना है। इस विभाग के माध्यम से मुझे 36 वर्षों से अधिक समय तक देश की सेवा करने का अवसर मिला, जिसमें मैंने आमूल-चूल परिवर्तन के साथ-साथ जल क्षेत्र से जुड़ी कई चुनौतियाँ भी देखीं।

मयूराक्षी बांध के संयुक्त नियंत्रण, तेनुघाट बांध सहित दामोदर घाटी में जलाशयों के एकीकृत संचालन और प्रस्तावित बालपहाड़ी बांध की स्थिति से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए 14.10.2022 को मेरी अध्यक्षता में एक अंतर-राज्यीय बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान, दोनों राज्यों (पश्चिम बंगाल और झारखंड) ने परियोजनाओं और उनके परिचालन पहलुओं पर अपना दृष्टिकोण रखा।

भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों में स्वच्छता/ स्वच्छता को संस्थागत बनाने और निर्भरता को कम करने के लिए लंबित संदर्भों के निपटान और स्वच्छता पर विशेष अभियान 2.0 02.10.2022 को शुरू किया गया था। एक महीने तक चलने वाला अभियान 31.10.2022 को समाप्त हुआ। के.ज.आ. के क्षेत्रीय कार्यालयों ने अभियान को एक विशाल सफल अभियान बनाने में अत्यधिक ध्यान दिया है। के.ज.आ. के अपर गंगा बेसिन संगठन के तहत अयोध्या स्थल पर कर्मचारियों और अधिकारियों ने स्वच्छता और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करके प्लास्टिक मुक्त परिसर बनाए रखने की शपथ ली। राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे ने अभियान के तहत खडकवासला बांध के तट पर सफाई अभियान चलाया।

मैं 10.10.2022 को एडिलेड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद (आईईसी) की 73वीं बैठक में तीन साल के कार्यकाल 2022-2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास आयोग(आईसीआईडी) का उपाध्यक्ष चुने जाने पर श्री कुश्विंदर वोहरा सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी) को हार्दिक बधाई देता हूं। आईसीआईडी के उपाध्यक्ष के रूप में, वह रणनीति और संगठन (पीसीएसओ) पर स्थायी समिति के सदस्य होंगे, जिसे सिंचाई और जल निकासी क्षेत्र में रणनीति विकसित करने, गतिविधियों और विशेष कार्यक्रमों के निर्माण के लिए सौंपा गया है।

भारत-यूरोपीय संघ जल साझेदारी (आईईडब्ल्यूपी) मार्च 2016 में ब्रुसेल्स में 13वें भारत-यूरोप शिखर सम्मेलन के दौरान यूरोपीय संघ और भारत सरकार द्वारा अपनाए गए 'भारत-यूरोपीय संघ जल साझेदारी (आईईडब्ल्यूपी) पर संयुक्त घोषणा' और जल सहयोग पर समझौता ज्ञापन का परिणाम है। अक्टूबर 2016 में यूरोपीय संघ और भारत सरकार के बीच हस्ताक्षर किए गए। 5वां भारत-ईयू जल मंच 27.10.2022 को नई दिल्ली में यूरोपीय संघ और भारत सरकार के जलशक्ति मंत्रालय के बीच एक दिवसीय उपस्थिति मंच के रूप में भारत-यूरोपीय संघ जल साझेदारी (आईईडब्ल्यूपी) के तहत आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में श्री कुश्विंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपीएंडपी) के साथ के.ज.आ. के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मैं, के.ज.आ. को जल सुरक्षित और समृद्ध भारत की दिशा में उसके भावी प्रयासों के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं सभी को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं।

डी एंड आर विंग के तहत गतिविधियाँ

पोलावरम सिंचाई परियोजना के कारण पड़ोसी राज्यों में जलमग्नता से संबंधित तकनीकी मुद्दे

पोलावरम सिंचाई परियोजना के कारण पड़ोसी राज्यों में जलमग्नता से संबंधित तकनीकी मुद्दों के संबंध में के.ज.आ. में 07.10.2022 को के.ज.आ. के अध्यक्ष डॉ आर.के. गुप्ता की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी। श्री जे. चंद्रशेखर अय्यर, सदस्य डी एंड आर भी बैठक में शामिल हुए, यह बैठक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 06.09.2022 के आदेशों के संबंध में 29.09.2022 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार की गई थी।

जयपुर में 10-12 अक्टूबर, 2022 को INCOLD द्वारा आयोजित "अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन" में तकनीकी पेपर प्रस्तुति

(क) श्री एन.एस. शेखावत, निदेशक, श्रीमती एम.एस. हर्षिता, उप निदेशक और आमिर सुहैल, सहायक निदेशक, एचसीडी (एन एंड डब्ल्यू) निदेशालय ने तकनीकी पेपर पेश किया और 10-12 अक्टूबर, 2022 तक जयपुर में सीबीआईपी और ड्रिप के सहयोग से आयोजित "अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन" में श्री एन.एस.शेखावत, निदेशक,एचसीडी (एन एंड डब्ल्यू) द्वारा तकनीकी पेपर प्रस्तुत किया गया। तकनीकी पेपर का विषय था “विसर्पित ढलान के कारण लगने वाले भारी पार्श्विक दाब से निपटना-शोंगटोंग कारचम एचईपी, हिमाचल प्रदेश, का एक केस अध्ययन”।

निदेशक, एचसीडी (एन एंड डब्ल्यू) द्वारा तकनीकी पेपर प्रस्तुति

(ख) श्री संजय कुमार सिब्बल, सीई, डिजाइन (एन एंड डब्ल्यू) यूनिट, श्री सतीश कंबोज, निदेशक और श्री घनश्याम पटेल, सहायक निदेशक, गेट्स डिजाइन (एन एंड डब्ल्यू) निदेशालय ने तकनीकी पेपर प्रस्तुत किया और INCOLD द्वारा सीबीआईपी और ड्रिप के सहयोग से 10-12 अक्टूबर, 2022 को जयपुर में आयोजित "अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन" में श्री सतीश कंबोज, निदेशक, गेट्स (एन एंड डब्ल्यू) द्वारा तकनीकी पेपर प्रस्तुत किया गया। तकनीकी पेपर का विषय था- सरदार सरोवर बांध, गुजरात के" झुके हुए पथ पर निष्क्रिय स्टॉपलॉग के प्रचालन प्रणाली में सुधार" । सरदार सरोवर बांध, गुजरात के तलहट में स्थित बिजलीघर(आरबीपीएच) के लिए अंतर्ग्राही स्टॉपलॉग 2008 से काम नहीं कर रहे थे। 1200 मेगावाट के बिजली घर के संचालन के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए इन स्टॉपलॉग का काम करना महत्वपूर्ण था।

निदेशक, एचसीडी (एन एंड डब्ल्यू) द्वारा तकनीकी पेपर प्रस्तुति

(ग) एचएसओ अधिकारियों ने 10-12 अक्टूबर,2022 के दौरान जयपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन में भाग लिया। श्री गोवर्धन प्रसाद, निदेशक, जल विज्ञान (सी), के.ज.आ. द्वारा "फुलर्टल से बदरपुर घाट तक बराक नदी के बल/मोड का विश्लेषण और परियोजना की योजना में इसके महत्व" पर एक पेपर प्रस्तुत किया गया था।

(घ) श्री अक्षत जैन, उप निदेशक, जलविज्ञान(एस) निदेशालय ने "भारत में मौजूदा नदी घाटी परियोजनाओं के डिजाइन बाढ़ और प्रेरक कारकों में देखे गए विचलन के विश्लेषण" पर एक पेपर प्रस्तुति दी है।

(ड़) श्रीमती पायल गोयल, उप निदेशक, जलविज्ञान(एस) निदेशालय ने " बहु तूफान विश्लेषण का उपयोग करके गांधी सागर बांध की डिजाइन बाढ़ समीक्षा" पर एक प्रस्तुति दी है।

(च) श्री योगेश कुमार गुप्ता (सहायक निदेशक), श्री अंकित कुमार (उप निदेशक) और श्री समीर कुमार शुक्ला (निदेशक) ने 10-12 अक्टूबर को जयपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन के लिए एक पत्र लिखा, जिसका शीर्षक था-"ऋषिगंगा नदी घाटी में 07.02.2021 को अचानक आई बाढ़ और मलबे के प्रवाह के बाद बनी झील की ब्रीच मॉडलिंग"। श्री योगेश कुमार गुप्ता, सहायक निदेशक, एफईएंडएसए,निदेशालय ने बांध सुरक्षा पर उपरोक्त अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 12.10.2022 को पेपर प्रस्तुत किया।

राजस्थान फीडर/इंदिरा गांधी नहर के विभिन्न मुद्दों का आकलन करने के लिए समिति

राजस्थान फीडर/इंदिरा गांधी नहर के विभिन्न मुद्दों का आकलन करने के लिए गठित समिति की पहली बैठक श्री जे चंद्रशेखर, सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ की अध्यक्षता में 27.10.2022 को सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ के चैंबर में आयोजित की गई थी।

एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया में 24वीं आईसीआईडी और 73वीं आईईसी बैठक में के.ज.आ. के अधिकारियों की भागीदारी

माननीय जल शक्ति मंत्री, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय जल आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया में 03-10 अक्टूबर 2022 के दौरान 24वें अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जलनिकास आयोग (आईसीआईडी) कांग्रेस और 73वें अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद(आईईसी)में भाग लिया।

इस आयोजन के दौरान श्री एन.एन. राय, निदेशक, जल विज्ञान(एस) ने " भारत की जल, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा-चुनौतियां और समाधान" पर एक पेपर प्रस्तुत किया और केंद्रीय जल आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक

टीम ने भारत के जल संसाधन विकास के संबंध में जलशक्ति मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों को भी प्रदर्शित किया।

केंद्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केंद्र (सीएसएमआरएस) की "स्थायी तकनीकी सलाहकार समिति (एसटीएसी)" की 37वीं बैठक

श्री जे. चंद्रशेखर, सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ की अध्यक्षता में सीएसएमआरएस, नई दिल्ली में 06.10.2022 को 37वीं एसटीएसी बैठक आयोजित की गई।

बैठक में सीएसएमआरएस की तकनीकी गतिविधियों और उपलब्धियों, सीएसएमआरएस के बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण, वित्तीय उपलब्धियों, कर्मचारियों की स्थिति, राजभाषा व ई-गवर्नेंस गतिविधियों, वर्षा जल संचयन प्रणाली तथा सौर ऊर्जा उत्पादन, सीएसएमआरएस की भविष्य की कार्य योजना (यानी बांध सुरक्षा अध्ययन में सीएसएमआरएस की भागीदारी, सीएसएमआरएस के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने आदि) के बारे में चर्चा हुई।

सरस्वती नदी पुनरुद्धार परियोजना, हरियाणा

सरस्वती नदी पुनरुद्धार परियोजना की प्रगति की समीक्षा करने और आदिबद्री बांध, सोम सरस्वती बैराज और सरस्वती जलाशय की निविदा ड्राइंग की तैयारी के लिए आवश्यक डेटा/जांच/डिजाइन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर आगे की कार्रवाई को सुनिश्चित करने के लिए 27.10.2022 को श्री जे. चंद्रशेखर अय्यर, सदस्य (डी एंड आर) के.ज.आ, की अध्यक्षता में के.ज.आ के समिति कक्ष में हाइब्रिड मोड में बैठक आयोजित की गई।
27.01.2022 को हुई पिछली चर्चा के खिलाफ कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) परियोजना प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष को प्रस्तुत की गई थी और आगे की चर्चा उन्हीं मदों पर हुई थी। परियोजना अधिकारियों और विभिन्न मदों पर

काम में शामिल विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई प्रस्तुतियों के अनुसार समय-सीमा को अद्यतन किया गया था।

बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (ड्रिप)-II योजना और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण मुद्दों से संबंधित समस्याओं पर चर्चा करने के लिए सचिव (जल संसाधन) की अध्यक्षता में बैठक

बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (ड्रिप), चरण-II और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक 18.10.2022 को श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में डॉ आरके गुप्ता, अध्यक्ष, के.ज.आ., अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव (आरडी एंड पीपी), संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, परियोजना निदेशक, ड्रिप-II और III और कार्यदल लीडर, विश्व बैंक ने भाग लिया।बैठक में, ड्रिप-II के लिए इंजीनियरिंग और प्रबंधन सलाहकार की नियुक्ति, बांध सुरक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना, एमएनआईटी- जयपुर के प्रस्ताव, सीपीएमयू के लिए अतिरिक्त जनशक्ति की आवश्यकता, क्षमता निर्माण, राज्यों को धनराशि निर्धारित करने के लिए सलाह और एनडीएसए द्वारा तैयार किए जाने वाले विनियमों की स्थिति आदि के बारे में चर्चा की गई।

रेणुकाजी बांध परियोजना, हिमाचल प्रदेश-भूवैज्ञानिक पहलुओं को सुलझाने के लिए के.ज.आ., जीएसआई और एचपीपीसीएल के बीच संयुक्त बैठक

रेणुकाजी बांध परियोजना से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 20.10.2022 को के.ज.आ, जीएसआई, सीएसएमआरएस और एचपीपीसीएल के अधिकारियों के बीच मुख्य अभियंता, डिजाइन (एन एंड डब्ल्यू), के.ज.आ की अध्यक्षता में एक ऑनलाइन बैठक हुई।

एचपीपीसीएल ने के.ज.आ को परियोजना डीपीआर, सीएसएमआरएस परीक्षण रिपोर्ट, जीएसआई रिपोर्ट आदि की प्रतियां प्रदान की थीं। के.ज.आ ने इन रिपोर्टों की जांच के आधार पर एचपीपीसीएल से कुछ स्पष्टीकरण मांगा है। स्पष्टीकरण मुख्य रूप से परियोजना भूविज्ञान और इसके निर्माण व संचालन चरण के दौरान बांध पर इसके प्रभाव तथा दीर्घकालिक आधार पर

परियोजना से परिकल्पित लाभों से संबंधित हैं।

साप्ताहिक रिपोर्ट

माननीय जल शक्ति मंत्रालय के कार्यालय को बांध की घटनाओं पर साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना

बांधों पर साप्ताहिक स्थितिजन्य रिपोर्ट संकलित की जा रही है और साप्ताहिक आधार पर माननीय जल शक्ति मंत्रालय के कार्यालय को प्रस्तुत की जा रही है। के.ज.आ के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अक्टूबर के महीने में निम्नलिखित बांध संबंधी घटनाओं की सूचना दी गई थी। दिनांक 13.10.2022 को उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में बूढ़ी राप्ती नदी के बढ़ते जल स्तर के कारण मदारहवा-अशोगवा तटबंध और अशोगवा-नगवा तटबंध टूटने की सूचना मिली थी।

एससीडीएस और एसडीएसओ के गठन पर बांधों और स्थिति का निरीक्षण

राज्य बांध सुरक्षा समिति (एससीडीएस) और राज्य बांध सुरक्षा संगठन (एसडीएसओ) के गठन/स्थापना और बांधों के राज्यवार किए गए निरीक्षणों की साप्ताहिक रिपोर्ट प्रत्येक शुक्रवार को जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग,जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत की जा रही है। 11.11.2022 तक राज्यों द्वारा बताया गया है कि वर्ष 2022 में 5334 बड़े बांधों में से 3907 बांधों का निरीक्षण किया गया है। बांध सुरक्षा अधिनियम (डीएसए), 2021 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार को बांध सुरक्षा पर राज्य समिति (एससीडीएस) और राज्य बांध सुरक्षा संगठन (एसडीएसओ) का गठन करना है। 11.11.2022 तक, 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने एससीडीएस का गठन किया है और 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने एसडीएसओ की स्थापना की है।

"बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021" की धारा 54 के तहत मसौदा नियम/विनियम तैयार करने के लिए उप-समिति की 7वीं बैठक

बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 की धारा 54 के तहत नियमों/विनियमों का मसौदा तैयार करने के लिए उप-समिति की 7वीं बैठक 28 अक्टूबर 2022 को श्री विजय सरन, सदस्य (नीति और अनुसंधान), एनडीएसए और मुख्य अभियंता (डीएसओ), के.ज.आ की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में आयोजित की गई थी। बैठक का एजेंडा मसौदा नियमों पर चर्चा करना और उन्हें अंतिम रूप देना था।

भद्रा बाँध, कर्नाटक

भद्रा बांध या लक्कवल्ली बांध, जिससे भद्रा जलाशय का निर्माण होता है, तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी भद्रा पर स्थित है। भद्रा बांध भारत में कर्नाटक के पश्चिमी भाग में भद्रावती और तारिकेरे की सीमा पर स्थित है। जलाशय भंडारण से 162,818 हेक्टेयर (402,330 एकड़) की सकल सिंचाई क्षमता, 39.2 मेगावाट की जल विद्युत उत्पादन (तीन बिजलीघर, दाएं और बाएं किनारे की मुख्य नहरों पर स्थित), पेयजल आपूर्ति और औद्योगिक उपयोग हेतु जल प्राप्त होता हैं। 1965 में चालू किया गया यह बांध 59.13 मीटर (194.0 फीट) ऊंची एक मिश्रित मिट्टी सह चिनाई संरचना है और शीर्ष स्तर पर 1,708 मीटर (5,604 फीट) लंबा है, जो 11,250.88 हेक्टेयर (27,801.5 एकड़) भूमि क्षेत्र को जलमग्न करती है।

जल आयोजना एवं परियोजना स्कन्ध के तहत गतिविधियां

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम परियोजना के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की चौथी बैठक

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम योजना के तहत परियोजनाओं को शामिल करने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की चौथी बैठक 18.10.2022 को सचिव (जल संसाधन) की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ और मुख्य अभियंता, पीएमओ, के.ज.आ ने भाग लिया।

बैठक के दौरान, 2021-2026 के दौरान कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम योजना के तहत उत्तराखंड राज्य की जमरानी बहुउद्देशीय परियोजना को शामिल करने के लिए चर्चा हुई। विचार-विमर्श के बाद, पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत परियोजना को शामिल करने के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की मंजूरी के बाद सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा जमरानी एमपीपी के मूल्यांकन के लिए समिति की सिफारिश की गई।

मयूराक्षी बांध के संयुक्त नियंत्रण, दामोदर घाटी में तेनुघाट बांध सहित जलाशयों के एकीकृत संचालन और प्रस्तावित बालपहाड़ी बांध की स्थिति के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अंतर-राज्यीय बैठक

मयूराक्षी बांध के संयुक्त नियंत्रण, तेनुघाट बांध सहित दामोदर घाटी में जलाशयों के एकीकृत संचालन और प्रस्तावित बालपहाड़ी बांध की स्थिति के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 14.10.2022 को के.ज.आ के अध्यक्ष डॉ. आर.के. गुप्ता की अध्यक्षता में एक अंतर्राज्यीय बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में के.ज.आ के वरिष्ठ अधिकारी, प्रधान सचिव, सिंचाई और जलमार्ग विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, सचिव, जल संसाधन, झारखंड सरकार के साथ-साथ दोनों संबंधित पार्टी राज्यों (पश्चिम बंगाल और झारखंड) के वरिष्ठ अधिकारियों और दामोदर घाटी निगम के अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक के दौरान, दोनों राज्यों ने परियोजनाओं और उनके परिचालन पहलुओं पर अपनी बात रखी। के.ज.आ द्वारा पूर्व में मांगे गए मयूराक्षी बांध के प्रासंगिक डेटा को पश्चिम बंगाल सरकार ने बैठक के दौरान आगे विचार-विमर्श के लिए 20 दिनों के भीतर प्रदान करने का आश्वासन दिया। यह भी निर्णय लिया गया कि डीवीसी प्रस्तावित बालपहाड़ी बांध सहित दामोदर घाटी परियोजनाओं का अनुकरण अध्ययन अगले 10 दिनों के भीतर पूरा कर लेगा।

बैठक के दौरान फूलबाड़ी में महानंदा बैराज की लागत को साझा करने के

लिए महानंदा बैराज पर महानंदा नदी के जल संसाधन आकलन पर भी चर्चा की गई। बिहार सरकार ने प्रस्तुति के माध्यम से अपनी बात रखी और पश्चिम बंगाल सरकार ने जल संसाधन मूल्यांकन को मजबूत करने के लिए उनके पास उपलब्ध प्रासंगिक डेटा को के.ज.आ को देने का आश्वासन दिया। महानंदा बैराज में महानंदा नदी के जल संसाधन मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के पास प्रासंगिक डेटा उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम बंगाल और बिहार सरकार के अधिकारियों के साथ वीसी के माध्यम से 10 दिनों के भीतर एक बैठक आयोजित करने की सलाह दी गई थी।

श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ को आईसीआईडी के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया

श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ को 10.10.2022 को एडिलेड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद (आईईसी) की 73वीं बैठक में तीन साल के कार्यकाल 2022-2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई और जल निकासी आयोग (आईसीआईडी) का उपाध्यक्ष चुना गया है।

आईसीआईडी के उपाध्यक्ष के रूप में, श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), कार्यनीति और संगठन स्थायी समिति (पीसीएसओ) के सदस्य होंगे, जिसे सिंचाई और जल निकासी क्षेत्र में कार्यनीति विकसित करने, गतिविधियों के निर्माण और विशेष कार्यक्रमों के लिए सौंपा गया है। वह सामरिक विषय के क्षेत्रों में से एक के कार्यनीति विषय नेता के रूप में भी कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त, वह राष्ट्रीय समितियों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने, सिंचाई और जल निकासी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में आईसीआईडी का प्रतिनिधित्व करने पर काम करेंगे।

5वां भारत-यूरोप जल मंच

भारत-यूरोपीय संघ जल भागीदारी (आईईडब्ल्यूपी) यूरोपीय संघ और भारत सरकार द्वारा 'भारत-यूरोपीय संघ जल भागीदारी पर संयुक्त घोषणा' का परिणाम है। यह भागीदारी मार्च 2016 में ब्रसेल्स में 13वें यूरोपीय-भारत संघ शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाई गई और अक्टूबर 2016 में यूरोपीय संघ और भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।भारत-यूरोपीय संघ जल भागीदारी (आईईडब्ल्यूपी) का उद्देश्य जल संसाधनों के अधिक स्थायी प्रबंधन और बढ़ती जनसंख्या, प्रतिस्पर्धी जल मांगों और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जल प्रबंधन द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए भारत और यूरोपीय संघ द्वारा साझा दृष्टि में योगदान करना है।में 5वां भारत-यूरोपीय संघ जल मंच आयोजित किया गया था। जल सहयोग पर 5वें भारत-यूरोपीय संघ जल मंच का उद्देश्य भारत और यूरोपीय संघ दोनों और इसके सदस्य देशों के हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला को एक साथ लाना है, जिसका उद्देश्य भारत और यूरोपीय संघ में जल क्षेत्र में अच्छी प्रथाओं, नियामक दृष्टिकोण, व्यापार समाधान और अनुसंधान और नवाचार के अवसरों पर विचारों का आदान-प्रदान करना है। इस कार्यक्रम में के.ज.आ के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी) और भारत सरकार के पदेन अतिरिक्त

सचिव ने भाग लिया । फोरम ने भारत-यूरोपीय संघ की साझेदारी की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने और इसके भविष्य के विकास पर विचार करने के लिए एक अद्भुत मंच के रूप में कार्य किया।

एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया में 24वीं आईसीआईडी और 73वीं आईईसी बैठक में के.ज.आ. के अधिकारियों की भागीदारी

अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई और जल निकासी आयोग (आईसीआईडी) का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जो सिंचाई और जल निकासी क्षेत्र के पेशेवरों का एक वैश्विक नेटवर्क है तथा 7 दशक के अधिक समय से भी अस्तित्व में है, और वर्षों से इसका स्वरूप कृषि जल प्रबंधन के तकनीकी, कृषि विज्ञान, सामाजिक आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण को अपनाकर केवल नहर सिंचाई के एक विशुद्ध इंजीनियरिंग रूप से एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन दृष्टिकोण तक विकसित हुआ है। वर्तमान में, आई सी आईडी में 80 सदस्य देश हैं।

माननीय जल शक्ति मंत्री की 5-6 अक्टूबर 2022 के सम्मेलन में उनकी भागीदारी के दौरान साथ देने और नवंबर, 2023 में विशाखापत्तनम में इसी तरह के आयोजन (25वीं कांग्रेस और 75वीं आईईसी) में आवश्यक सुविधाओं और अन्य रसद का आकलन करने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने हेतु श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ और भारत सरकार के पदेन अतिरिक्त सचिव, ने के.ज.आ के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 3-10 अक्टूबर 2022 के दौरान आईसीआईडी के 24वें कांग्रेस और 73वें आईईसी में भाग लिया।

आयोजन के दौरान, माननीय मंत्री और सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ ने इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले विदेशी प्रतिनिधियों जैसे सऊदी अरब, उज्बेकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधिमंडल के साथ कई बैठकें आयोजित की। माननीय मंत्री और सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ द्वारा भारत में संचालित ऑस्ट्रेलियाई उद्योग 'ऑस्ट्रेड' के साथ एक गोलमेज बैठक भी आयोजित की गई थी।

इसके अलावा, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी) ने संगोष्ठी- I के दौरान भविष्य में सिंचाई प्रबंधन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण पर "सिंचाई के बुनियादी ढांचे का प्रदर्शन" शीर्षक का पेपर प्रस्तुत किया। उन्होंने उपसमूहों में विभिन्न प्रस्तुतियों में भी भाग लिया और तकनीकी चर्चाओं में भाग लिया। श्री नित्यानंद राय, निदेशक, के.ज.आ और श्री सुनील कुमार, निदेशक, के.ज.आ द्वारा क्रमश:"भारत की जल, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा-चुनौतियां और समाधान" तथा "महाराष्ट्र के सूखा प्रवण क्षेत्रों में गैर-पारंपरिक पानी का उपयोग करके उपसतह ड्रिप सिंचाई की संभावनाएं" पर पत्र प्रस्तुत किए गए।

सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी) (और 25वीं कांग्रेस की आयोजन समिति के अध्यक्ष भी) ने आईसीआईडी की प्रस्तावित 25वीं कांग्रेस और 75वीं आईईसी के बारे में एक प्रस्तुति दी, जिसमें कांग्रेस के तकनीकी विवरण, विशाखापत्तनम में उपलब्ध सुविधाओं और तकनीकी दौरे के विवरण पर प्रकाश डाला गया।

आयोजन के दौरान, उन्हें आगे तीन साल की अवधि के लिए आईसीआईडी की एक समिति सी-कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया।

★ ★ ★

याः सूर्यो रश्मिभिराततान याम्य इन्द्री अरदद् गातुभूर्मिम्।
तो सिन्धवो वरिवो धातना नो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः।।

हिंदी अर्थ:- जिस जल को सूर्यदेव अपनी रश्मियों (किरणों) के द्वारा बढ़ाते हैं एवं इन्द्रदेव के द्वारा जिन्हें प्रवाहित (प्रवाह) होने का मार्ग दिया गया है, आप उन जलधाराओं से हमें धन-धान्य से परिपूर्ण करें तथा कल्याणप्रद साधनों से हमारी रक्षा करें।

आरएम विंग के तहत गतिविधियां

आयन क्रोमैटोग्राफ पर कार्यशाला

के.ज.आ की प्रयोगशालाओं और के.ज.आ में आवश्यक सहायक उपकरणों के लिए आयन क्रोमैटोग्राफ की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए 20.10.2022 को समिति कक्ष, सेवा भवन, नई दिल्ली में आयन क्रोमैटोग्राफ पर एक कार्यशाला आयोजित की गई थी।

श्री पी.एम.स्कॉट, सदस्य(आरएम) ने अपने उद्घाटन भाषण में बढ़ते शहरीकरण और औद्योगीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के कारण जल गुणवत्ता निगरानी पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया। इन चुनौतियों के लिए साइट से प्रयोगशाला तक, सभी स्तरों पर जल गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क के आधुनिकीकरण की आवश्यकता है।

आयन क्रोमैटोग्राफ यंत्र पर पहली प्रस्तुति थर्मो फिशर साइंटिफिक ने दी थी।

दूसरी प्रस्तुति मेट्रोहम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने दी। दूसरे पहर के आधे दिन में, के.ज.आ की प्रस्तुति के बाद, रासायनिक विश्लेषण में आयन क्रोमैटोग्राफ के उपयोग से संबंधित प्रस्तुतियां भी संगठनों यानी एनआईएच रुड़की, सीजीडब्ल्यूबी, एनपीएल द्वारा दी गईं।

31.10.2022 तक योजनाओं की वित्तीय प्रगति

(राशि करोड़ में और विशिष्टत: कें.ज.आ. के घटक के लिए)

क्रमांक	योजना/घटक का नाम	बजट अनुमान 2022-2023	व्यय	व्यय (%में)
1.	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास (डीडब्ल्यूआरआईएस)	185.00	87.8386	47.48%
2.	जल संसाधन विकास योजनाओं की जांच (आईडब्ल्यूआरडी)	08.000	6.2907	78.63%
3.	बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)	23.203	5.5163	23.77%
4.	निर्देशन एवं प्रशासन (डी एंड ए) - प्रमुख कार्य और ओई (एसएपी)	11.15	4.746	42.56%
5.	राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजना (एनएचपी)	44.37 (RE)	10.7157	24.15%
6.	बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) चरण-II	100.00	0.940	0.94%

जलाशय निगरानी

के.ज.आ साप्ताहिक आधार पर देश के 143 जलाशयों की सजीव भंडारण स्थिति की निगरानी कर रहा है और प्रत्येक गुरुवार को साप्ताहिक बुलेटिन जारी कर रहा है। इन जलाशयों में से 46 जलाशयों में 60 मेगावाट से अधिक की स्थापित क्षमता वाले जलविद्युत लाभ हैं। इन 143 जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता 177.464 बीसीएम है जो देश में अनुमानित 257.812 बीसीएम की संग्रहण क्षमता का लगभग 68.83% है।

जलाशय भंडारण बुलेटिन दिनांक 27.10.2022 के अनुसार, इन जलाशयों में उपलब्ध कुल सजीव भंडारण 158.451 बीसीएम है जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 89% है। हालांकि, पिछले साल इसी अवधि के लिए इन जलाशयों में उपलब्ध कुल संग्रहण 142.296 बीसीएम था और पिछले 10 वर्षों का औसत संग्रहण 135.489

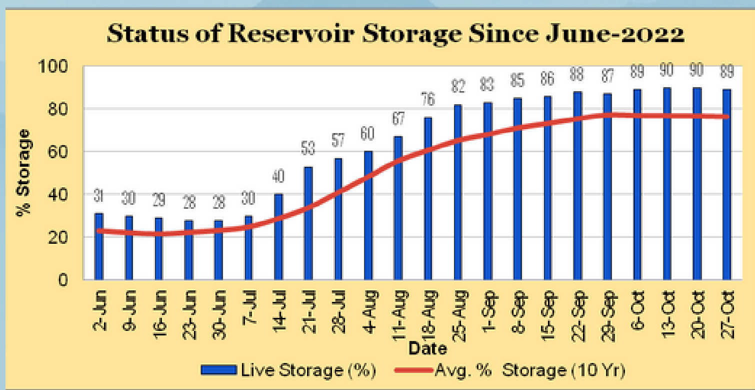

बीसीएम था। इस प्रकार, दिनांक 27.10.2022 के बुलेटिन के अनुसार 143 जलाशयों में उपलब्ध जल संग्रहण पिछले वर्ष की इसी अवधि के जल संग्रहण का 108% और पिछले दस वर्षों के औसत संग्रहण का 113% है।

देश में बाढ़ की स्थिति-अक्टूबर 2022

ब्रह्मपुत्र और बराक और झेलम बेसिन में 01.05.2022 को नियमित बाढ़ पूर्वानुमान गतिविधि शुरू हुई। 1 मई से 31अक्तूबर 2022 की अवधि के दौरान, 11344 बाढ़ पूर्वानुमान (6773 स्तर और 4571 प्रवाह) जारी किए गए थे, जिनमें से 10669(6471 स्तर और 4198प्रवाह) पूर्वानुमान 94.02% की प्रतिशत सटीकता की सीमा के भीतर थे। केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से 31अक्तूबर 2022 तक 116 रेड बुलेटिन (चरम बाढ़ की स्थिति के लिए) और 121 ऑरेंज बुलेटिन (बाढ़ की गंभीर स्थिति के लिए) जारी किए गए।

01.05.2022 से 31.10.2022 के दौरान बाढ़ की स्थिति का सारांश

चरम बाढ़ की स्थिति

ग्यारह बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों ने चरम बाढ़ की स्थिति देखी:

क्र.सं.	राज्य	जिला	नदी	स्टेशन	अवधि	
					से	तक
1.	असम	नगांव	कोपिली	कामपुर	15/05/2022 1600 बजे 16/06/2022 1600 बजे	21/05/2022 2000बजे 22/06/2022 1600बजे
2.	बिहार	किशनगंज	महानंदा	तैयबपुर	29/06/2022 0400 बजे	29/06/2022 0800 बजे
3.		सुपौल	कोसी	बसुआ	02/08/2022 1900 बजे	02/08/2022 2200 बजे
4.		शिवान	घागरा	दारौली	14/10/2022 0600 बजे	16/10/2022 2200 बजे
5.	तेलंगाना	भूपालपल्ली	गोदावरी	कालेश्वरम	14/07/2022 0600बजे	15/07/2022 1200बजे
6.		कुमारमभीम	वर्धा	सिरपुर(टी)	14/07/2022 0300 बजे	17/07/2022 0200बजे
7.	आंध्र प्रदेश	अल्लूरी सीतारामराजू	साबरी	चिंटुरु	15/07/2022 0100बजे	19/07/2022 1000बजे
8.	राजस्थान	करौली	चंबल	मंडरियल	25/08/2022 0400 बजे	25/08/2022 1100 बजे
9.		धौलपुर	चंबल	धौलपुर	25/08/2022 0600बजे	26/08/2022 0700बजे
10.	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर	राप्ती	बलरामपुर	08/10/2022 1100 बजे	13/10/2022 1900 बजे
11.		सिद्धार्थनगर	राप्ती	बंसी	14/10/2022 1600बजे	19/10/2022 0900 बजे

80 बाढ़ निगरानी स्टेशन पर चरम बाढ़ की स्थिति देखी।

बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों के लिए गंभीर बाढ़ की स्थिति

95 बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों पर गंभीर बाढ़ की स्थिति देखी असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, एनसीटी दिल्ली और गुजरात।

सामान्य बाढ़ की स्थिति से ऊपर

असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ओडिशा, तेलंगाना ,राजस्थान और कर्नाटक में 46 बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों पर बाढ़ की स्थिति सामान्य से ऊपर देखी गई।

सीमा से अधिक प्रवाह वाले जलाशय

आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, झारखंड, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 86 जलाशयों में उनकी सीमा से अधिक जल प्रवाह हुआ।

शोध पत्र प्रस्तुत करने पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) निदेशकों के साथ बैठक

सदस्य (नदी प्रबंधन), के.ज.आ की अध्यक्षता में नई दिल्ली में और साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 31.10.2022 को निम्नलिखित पर चर्चा करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई:

- डेटा अनुरोध में इंगित समय-सीमा के अनुसार डेटा मांगने वाली संस्था द्वारा "डेटा उपयोगिता प्रमाणपत्र" प्रस्तुत किया जाना है।
- "डेटा विलोपन प्रमाण पत्र" डेटा मांगने वाली संस्था द्वारा प्रस्तुत किया जाना है कि के.ज.आ से प्राप्त कच्चे डेटा को नष्ट कर दिया गया है।

बैठक के दौरान, निदेशक, के.ज.आ ने विभिन्न आईआईटी के प्रतिनिधियों के साथ मामला दर मामला बातचीत/चर्चा शुरू की। पिछले शोध पत्र/डेटा उपयोग प्रमाण पत्र/डेटा विलोपन प्रमाण पत्र जमा करने पर इन कई बिंदुओं पर चर्चा की गई।
अंत में, आईआईटी को यह सुझाव दिया गया कि यदि अध्ययन अभी भी चल रहे हैं, तो एक अंतरिम रिपोर्ट के.ज.आ को प्रस्तुत की जानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुरोधित डेटा का उचित उपयोग किया जा रहा है और अध्ययन समय पर पूरा हो जाएगा।

जल क्षेत्र-समाचार

- स्वच्छ गंगा मिशन : यूपी में 308.09 करोड़ रुपये की चार परियोजनाएं मंजूर (अमर उजाला, 02.10.2022)
- ग्रामीण घरों में से 74 प्रतिशत को सातों दिन पानी की आपूर्ति मिलती है : अध्ययन (राष्ट्रीय सहारा, 03.10.2022)
- नदियों के संरक्षण पर करीब 20 हजार करोड़ खर्च होंगे (हिन्दुस्तान, 05.10.2022)
- जल जीवन मिशन से हर साल 1.36 लाख बच्चों की जान बचाएगा भारत (अमर उजाला, 12.10.2022)
- राजस्थान व मध्य प्रदेश में जल बंटवारे का विवाद होगा खत्म (राजस्थान पत्रिका, 17.10.2022)
- गंगा की निर्मलता को लेकर गंगादूत का प्रशिक्षण संचालित (पायनीयर, 19.10.2022)
- पाकिस्तान से जल विवाद का आकलन करेगा भारत (हिन्दुस्तान, 20.10.2022)
- रसायन डाल कर यमुना को साफ करना कोई स्थायी हल नहीं (जनसत्ता, 29.10.2022)
- यमुना अब तक मैली क्यों, एनजीटी में प्राधिकरणों को देना होगा जवाब (नवभारत टाईम्स, 30.10.2022)
- उपलब्धि : गुजरात में नल से जल योजना का लक्ष्य 100 फीसदी पूरा (राजस्थान पत्रिका, 31.10.2022)

अन्य गतिविधिया

डेटा कॉर्नर- के.ज.आ. बेसिन

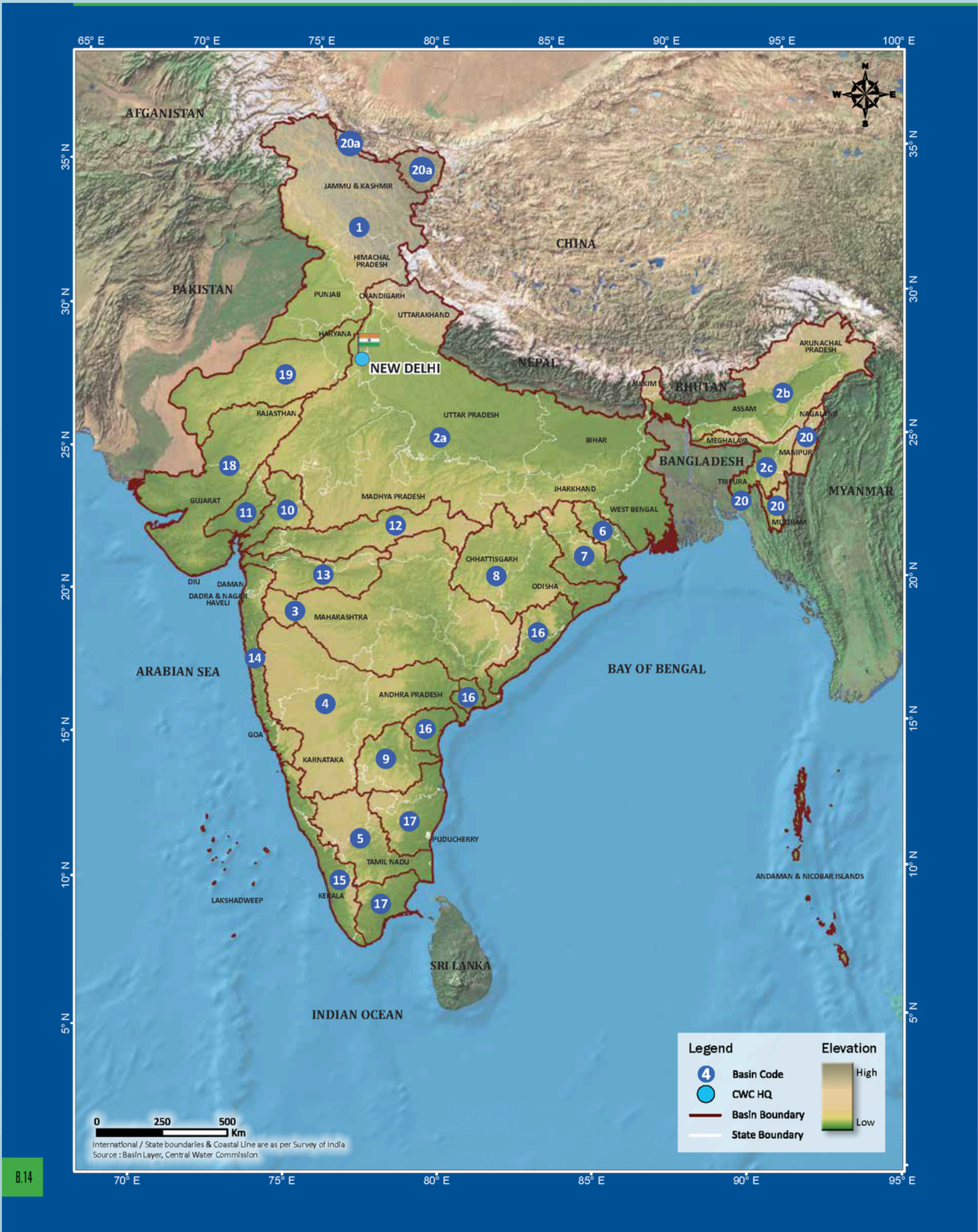

गैलरी

स्वच्छता विशेष अभियान 2.0 के तहत 18/10/2022 को हेसरगट्टा झील और आसपास की सफाई

20/10/2022 को कोलार में केसी घाटी परियोजना का निरीक्षण (पीएमकेएसवाईएचकेकेपी- एसएमआई के लिए माध्यमिक उपचारित पानी से टैंक भरने की योजना)।

राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिज्ञा

भोपाल

भुवनेश्वर

कालिंदी भवन, नई दिल्ली

लखनऊ

17000 फीट की ऊंचाई पर युमेसमडोंग (जीरो प्वाइंट के पास) और गुरुडोंगमार झील (18000 फीट की ऊंचाई) पर बर्फ प्रमापी केंद्रों की स्थापना के लिए सिक्किम सरकार और के.ज.आ, उत्तरी सिक्किम के वन अधिकारियों का संयुक्त दौरा।

दिनांक 18.10.2022 प्रो. रीता बहुगुणा जोशी जीकी अध्यक्षता मेंसंसदीय राजभाषा समितिने अहमदाबाद मेंउपमंडलीय अभियंता काकार्यालय, केंद्रीयजल आयोग, अहमदाबाद के साथनिरीक्षण बैठक की|

इतिहास- महानदी जलाशय परियोजना

महानदी जलाशय परियोजना (जिसे अब पं. रविशंकर सागर के नाम से जाना जाता है) महानदी नदी पर एक प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है जो मध्य प्रदेश में रायपुर जिले के दक्षिण-पूर्वी कोने में फरसिया गाँव से निकलती है। स्थिर पानी वाला एक छोटा तालाब, पास में एक मंदिर और चारों ओर खेती की जमीन इस महान नदी के उद्गम स्थल को चिह्नित करती है। यह परियोजना धमतरी जिले में मौजूद रूद्री बांध से लगभग 5 किमी ऊपर की ओर गंगरेल गांव में स्थित है। परियोजना स्थल रायपुर से सड़क मार्ग से 93 किमी दूर है। इसका जलग्रहण क्षेत्र 3670 वर्ग किमी है और इसमें 909 मिलियन घन मीटर पानी समाहित है।

महानदी बेसिन परियोजना के प्रतिप्रवाह में मुरुमसिल्ली और दुधवा नाम के दो मौजूदा जलाशय हैं। इन जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता 1315 एमसीएम है जो महानदी जलाशय परियोजना तक कुल जलग्रहण क्षेत्र की 75% निर्भर उपज के लगभग बराबर है।

निर्माण का चरणबद्ध कार्यक्रम

परियोजना के प्रथम चरण में निम्नतम नींव स्तर से अधिकतम 32 मीटर की ऊंचाई वाले समग्र बांध का निर्माण और 42 किमी लंबाई की एक फीडर नहर का निर्माण शामिल है जो मौजूदा तांदुला मुख्य नहर के साथ हेड-वर्क्स को जोड़ता है। भिलाई इस्पात संयंत्र की 2.5 मिलियन टन से 4 मिलियन टन तक प्रस्तावित विस्तार की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसमें 20 घन मीटर प्रति सेकंड की जल वहन क्षमता है। 1969 के अनुमान के अनुसार इस परियोजना की लागत 15.34 करोड़ रुपये आंकी गई थी। परियोजना के दूसरे चरण में मौजूदा महानदी नहर प्रणाली में नहरों का पुनर्निर्माण करना और दो प्रणालियों के तहत नए क्षेत्रों की अतिरिक्त सिंचाई करने के लिए फीडर नहर से वितरिकाओं और छोटी निकासी का निर्माण शामिल है। इसने मौजूदा 1.414 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 0.8888 लाख हेक्टेयर क्षेत्र संवर्धन किया।

बांध के लिए आधारशिला 5 जून 1972 को प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा रखी गई थी। परियोजना के चरण । के लिए पूर्व निर्माण कार्यों की योजना बनाने के लिए स्केलेटन संगठन को जनवरी 1973 में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था।

मुख्य मृदा बांध

मिट्टी के बांध में एक समरूप खंड शामिल है,और इसे परियोजना के आसपास उपलब्ध मिट्टी के गुणों को ध्यान में रखते हुए मितव्ययता के साथ डिजाइन किया गया है। केंद्रीय अंतर्भाग के नीचे की ओर एक ऊर्ध्वाधर चिमनी नाली प्रदान की गई है। प्रतिप्रवाह ढलानों में स्थिरता लाने के लिए केंद्रीय अंतर्भाग के 4 मीटर ऊर्ध्वाधर अंतराल पर क्षैतिज रेत फिल्टर प्रदान किए गए हैं। मृदा बांध की उचित जल निकासी उसकी जीवन रेखा है और उसे न केवल तब अच्छी तरह से काम करना चाहिए जब जलाशय भर जाता है बल्कि जब यह कम हो जाता है तो इस तरह के काम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मिट्टी का कुल काम लगभग 22 लाख घन मीटर है और भारी भू-चालित उपकरणों जैसे स्क्रेपर्स, डोजर और स्पंदनात्मक संहनन उपकरणों की मदद से विभागीय रूप से पूरा किया गया है।

मॉडल अध्ययन

राज्य सिंचाई विभाग, भोपाल के जलीय अनुसंधान केंद्र में उत्प्लाव मार्ग रूपरेखा की और ऊर्जा प्रसारक (रोलर बकेट) के डिजाइन की उपयुक्तता की पुष्टि के लिए मॉडल अध्ययन पूरा कर लिया गया है।

महानदी जलाशय परियोजना (विशेषताएँ एक नजर में)			
स्थान : मध्य प्रदेश में रायपुर जिलों की धमतरी तहसील में मौजूदा रुद्री वीर से लगभग 5 किमी ऊपर डंगरेल गांव में महानदी नदी पर दो चरणों में एक बांध।			
चिनाई बांध			
	उत्प्लाव मार्ग भाग की लंबाई	:	252.25 मी,
	अप्रवाही भाग की लंबाई	:	222.50 मी,
	अधिकतम ऊँचाई	:	32.00 मी,
	उत्प्लाव मार्ग गेट्स	:	14 (15 मी, x 10 मी,)
	बांध की शीर्ष चौड़ाई	:	7.5 मी,/6.5 मी,
जल विज्ञान			
	जलग्रहण - क्षेत्र	:	3670वर्गकिमी,
	औसत वार्षिक वर्षा	:	1430 मिलि.मी,
मृदा बाँध			
	मुख्य बांध की लंबाई	:	1245.75 मी,
	काठी बांध की लंबाई	:	1110.00 मी,
	अधिकतम ऊँचाई	:	30.50 मी,
प्रस्तरपूर बाँध			
	लंबाई	:	130.00 मी,
	अधिकतम ऊँचाई	:	10.00 मी,
जलाशय			
	सकल भंडारण क्षमता	:	909.30 लाख घन मीटर,
	सजीव भंडारण	:	765.70 लाख घन मीटर,
पोषक नहर : लंबाई		:	42 किमी,
नहर : लंबाई		:	51.2 किमी,
लाभ			
	चरण- I		
	(i) भिलाई इस्पात संयंत्र को वार्षिक जलापूर्ति	:	255 लाख घन मीटर, (9 000 लाख घन फीट)
	(i) रबी सिंचाई	:	40469 हेक्टेयर (एक लाख एकड़)
	चरण– II		
	(i) मौजूदा महानदी नहर प्रणाली/तांदुला के तहत	:	1.414 लाख हेक्टेयर (3.5 लाख एकड़)
	(i) फीडर नहर के तहत: 0.32724 लाख हेक्टेयर (0.8 लाख एकड़) चरण -1 के तहत भिलाई स्टील प्लांट और उसके सहायक उद्योगों को पानी की आपूर्ति से 96 लाख रुपये का वार्षिक राजस्व प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है।		
लागत :	चरण -I	:	रु.15.34 करोड़
	चरण -II	:	रु.10.00 करोड़
प्रारंभ होने की तिथि		:	1972-73
पूरा होने की तारीख		:	1978

मुख्य उत्प्लाव मार्ग

उत्प्लाव मार्ग में प्रत्येक 15 मीटर स्पष्ट चौड़ाई के 14 बे शामिल हैं। शिखर के ऊपर 15 मीटर x 10 मीटर आकार के चौदह त्रिज्य शिखर फाटक स्थापित किए जाएंगे। उत्प्लाव मार्ग को प्रति सेकंड 23500 घन मीटर की चरम बाढ़ को सहन करने के अनुसार डिजाइन किया गया है। मध्यम बाढ़ डिजाइन उत्प्लाव मार्ग 17890 घन मीटर प्रति सेकंड तक बाढ़ को सहन कर सकता है। नींव के निचले स्तर पर शिखर तक उत्प्लाव मार्ग की अधिकतम ऊंचाई लगभग 16 मीटर है। उत्प्लाव मार्ग नींव में मुख्य रूप से क्वार्टजाइट और क्वार्टजेटिक बलुआ पत्थर होते हैं, जो कमजोर शैल सीमों के करीबी अंतराल पर होते हैं। अपक्षय हुए तलहट में मिट्टी की भराई की गई है।

प्रगति (अक्टूबर 1975 तक)

5 किमी की लंबाई में रुद्री से बांध स्थल तक पहुंचने की सड़क, जिसमें चार पुल और पुलिया शामिल है उसे एक कार्य सत्र के रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है। रुद्री और बांध स्थल के नियमित और वर्कचार्ज कर्मचारियों के लिए परियोजना कॉलोनियां आ गई हैं। कंट्रोल रूम चालू कर दिया गया है। परियोजना स्थल पर स्कूल, अस्पताल, आंतरिक परिवहन, एंबुलेंस आदि की व्यवस्था की गई है।

इस परियोजना का निर्माण 1973 में शुरू किया गया था। भारत सरकार द्वारा इस परियोजना से जुड़ी उच्च प्राथमिकता को देखते हुए कोई पूर्व निर्माण समय नहीं दिया गया था क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट का विस्तार कार्यक्रम इसके समय पर पूरा होने के साथ जुड़ा हुआ था। इसलिए, डिजाइन और निर्माण कार्य को लगभग एक साथ आगे बढ़ना था।

उत्प्लाव मार्ग की नींव और गैर-उत्प्लावी चिनाई बांध की नींव के लिए खुदाई पूरी होने वाली थी। उत्प्लाव वाहिका में खुदाई का काम पूरा हो गया है। विभागीय स्तर पर मिट्टी हटाने वाली भारी मशीनों की मदद से मुख्य मृदा बांध पर मिट्टी का काम चल रहा था और बाएं किनारे पर उपलब्ध सीमित क्षेत्र में

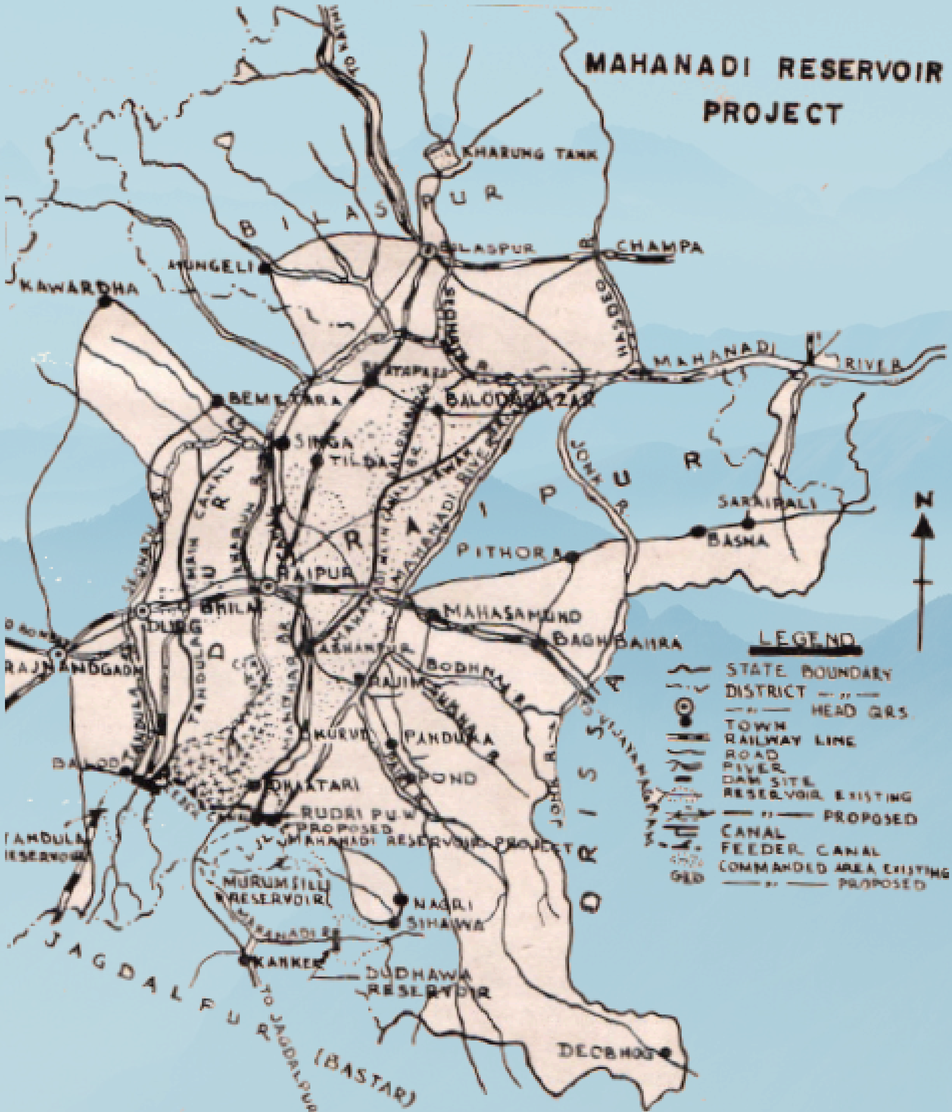

प्रतिदिन लगभग 3000 घन मीटर मिट्टी का काम किया जा रहा था। पोषक नहर की 42 किमी की पूरी लंबाई के लिए संरेखण का सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें से 36 किमी की लंबाई के लिए संरेखण को मंजूरी दी गई है। 33 किमी की लंबाई पर काम चल रहा है। इस प्रकार विभागीय एजेंसियों, उजरती मजदूर और ठेकेदारों को नियोजित करके पूरी परियोजना पर बड़े पैमाने पर काम शुरू किया गया। मार्च 1975 के अंत तक किया गया सकल व्यय 9.87 करोड़ रुपये और शुद्ध व्यय 7.53 करोड़ रुपये था। इससे निर्माण की तेज गति और स्थल पर लागत का अंदाजा हो जाएगा।

चरण-द्वितीय के कार्यों को भी साथ-साथ शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि नहर प्रणाली अतिरिक्त क्षेत्रों की सिंचाई के लिए पानी ले जा सके जो परियोजना के चरण I के पूरा होने के बाद न्यूनतम समय अंतराल के साथ यथासंभव तैयार हो सके।

चरण-I को पूरा करने की लक्ष्य तिथि दिसंबर 1975 रखी गई है। इस परियोजना के पूरा होने से जाहिर तौर पर देश में स्टील के उत्पादन में मदद करने के अलावा चावल के राज्य कहे जाने रायपुर और दुर्ग जिले के लोगों के लिए समृद्धि की एक नई शुरुआत होगी।

((स्रोत: भागीरथ अक्टूबर 1975)

केंद्रीय जल आयोग
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का एक सम्बद्ध कार्यालय

संपादक मंडल
- श्री समीर चटर्जी, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) - मुख्य संपादक
- श्री योगेश पैथंकर, मुख्य अभियंता(पीएमओ) - सदस्य
- श्री अभय कुमार, निदेशक(नदी प्रबंध समन्वय) - सदस्य
- श्री एस.के. राजन, निदेशक(टीसी & ज.प्र.अभि.) - सदस्य
- श्री भूपिन्द्र सिंह, निदेशक(डब्ल्यूपीएंडपी–सी)- सदस्य
- श्री अर्जेश कुमार मधोक, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.) - सदस्य
- श्री आर.के. शर्मा, उप निदेशक(डीएण्डआर सम.) - सदस्य
- श्री कैलाश के. लाखे, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.) - सदस्य सचिव
- हिन्दी अनुवाद - श्रीमति मीना कुमारी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

अभिकल्प एवं प्रकाशन
**जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केन्द्रीय जल आयोग**
**द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110 066
ई-मेल: media-cwc@gov.in**